वृहत सिंचाई/विद्युत योजना स्वीकृति के लिए सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के निर्माण से कितने आदिवासियों के प्रभावित होने की और इसकी डूब में कितने वृक्षों और गावों के आने की संभावना है ;

(ग) डूब के अधीन अनुमानत: कितने मूल्य की भूमि और वन सम्पदा के आने की संभावना है ;

(ध) उक्त परियोजना के निर्माण से डूब में आने वाले प्रभावित आदिवासियों के पुनर्वास के लिए प्रस्तावित प्रबंधों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार ने इन योजनाओं को स्वीकृति देते समय पर्यावरण संबंधी पहलुओं पर भी विचार किया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार बस्तर जिले की कोई वृहत सिंचाई परियोजना, अनुमोदन के लिए लम्बित नहीं पड़ी है । तथापि, मध्य प्रदेश के बस्तर जिले की बोधघाट जल विद्युत परियोजना के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन केन्द्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के अनुमोदन की प्रतीक्षा है ।

(ख) बोधघाट परियोजना से प्रभावित लगभग 8, 875 लोगों की कुल आबादी में से 6,209 व्यक्ति अनुसूचित जाति तथा 733 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के हैं । इस परियोजना के निर्माण से 42 गांव या तो पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से प्रभावित होंगे । यह अनुमान लगाया गया है कि 21 सेंटीमीटर आकार के 22 लाख और इससे अधिक वृक्षों पर इसका प्रभाव पड़ेगा ।

(ग) इससे जलमग्न होने वाली संभावित भूमि व वनों की लागत इस बात पर निर्भर करेगी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत अन्तिम रूप से कितना मुआवजा दिया जाना है । तथापि, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, 1983 में भूमि के लिए 15.4 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है ।

(घ) परियोजना प्राधिकारियों द्वारा तैयार किए गए पुनर्वास कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक विस्थापित परिवार को बिना किसी प्रकार की लागत के 2 हेक्टेयर (5 एकड़) का एक विकसित प्लाट, जोकि कृषि योग्य होगा के साथ-साथ नए पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत बिना किसी लागत के एक मकान जिसमें पशुओं को बांधने के लिए पर्याप्त खुला स्थान (500 वर्गमीटर क्षेत्रफल का प्लाट) आदि आवंटित किया जाएगा । जिन लोगों का पुनर्वास किया जाएगा उनको अन्य सुविधाएं यथा स्कूल एवं पीने का पानी आदि भी उपलब्ध कराया जाएगा ।

(ङ) जी हां, । इस प्रकार की स्कीमों का अनुमोदन करने से पूर्व सरकार पर्यावरण की दृष्टि से सभी पहलुओं पर विचार करती है ।

Production of 'Chlorine' Technical Tablets

1423. SHRI ASHOK NATH VERMA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state

(a) whether 'chlorine technical and tablets, one of the effective sources and important measures for desinfecting impure water at house hold level, are in short supply in the country; and

(b) what is the total annual requirement of 'chlorine' technical/ tablets in the country; its actual annual production, names and addres ses of manufacturers and price fixed for the same and subsidy; if any, given for its production?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) and (b) Disinfecting of water for supply to households is done by Municipalities using liquid chlorine which is easily available in the country. 'Chlorine tablets', which are being manufactured in the country in the

Bmall scale sector are only an addi tional source of disinfecting for households. Government do not monitor its production and as such, figures regarding its demand production and name of companies manufacturing it are not available. Further, the item is not price controlled and, there is no subsidy on it.

Representation for thy Repair and Renovation of Varanasi Post Office Building

1424. SHRI SAMAR MUKHER-JEE: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state;

(a) whether a representation dated the 21st June, 1988 from Jangambadi (Bangalitola) Post Office Bachao Sanghorsh Samiti, Varanasi has been received regarding repair and reno vation of post office building which was acquired by Government; and

(b) if so, what steps Government have taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI GIRIDHAR GOMANGO); (a) Yes, Sir.

(b) Instructions have been issued to the concerned subordinate authorities to prepare and sanction estimates for essential repairs etc. immediately so that the work could start forthwith.

Problems of Vellangailore Telephone Subscribers

1425. SHRI SAMAR MUKHER-JEE: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state;

(a) whether a representation dated the 4th July, 1988 has been received from a public representative about the problems being faced by Vellan gailore (Kerala) telephone subscribers and the staff of local telephone exchange;

(b)' whether the said representation was in reply to Ministry's communication dated 19th May, 1988 on the problems; and

(c) whether his Ministry is reviewing the issues; if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) The issues are under examination and a reply will be sent to the Hon'ble Member.

E. D. post Masters in Assam

1426. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the total number of Extra Departmental employees serving as Post Masters in the rural post offices in Assam;

(b) what is the nature of pay of these employees and prospect in service;

(c) whether there is any provision for the absorption in regular postal service Or this category of Extra-Departmental employees; and

(d) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI GIRIDHAR GOMANGO); (a) The number of E. D. postmasters in North Eastern Circle as on 31-3-88 8is as under :

E.D Sub-Postmasters	56
E.D. Branch Postmasters	4780

(b) These Extra Departmental employees being part-time employees get a basic allowance between a minimum and a maximum. The allowances paid to them are given below:

		Min	Max
EDSPM	Eis.	385	620
EDBPM	Rs.	275	440